यूपीएस पर भी अब मिलेगा टैक्स लाभ

मौजूदा एनपीएस कर्मचारियों को भी स्विच का विकल्प

सरकार देगी 18 .5 प्रतिशत का सुनिश्चित योगदान

वित्त मंत्रालय ने एनपीएस जैसी छूट की मंजूरी दी

नई दिल्ली, 4 जुलाई.वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत वर्तमान में उपलब्ध सभी कर लाभ अब नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर भी लागू होंगे.

यह निर्णय यूपीएस को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे दोनों पेंशन विकल्पों के बीच समानता स्थापित होगी.एकीकृत पेंशन योजना को इस वर्ष की शुरुआत में एनपीएस के एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है. इसके साथ ही, मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, जो पहले से ही एनपीएस के तहत आते हैं, को भी नई योजना में स्विच करने का एकमुश्त विकल्प दिया गया है. इस नई पेंशन योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने मार्च 2025 में आवश्यक नियम और विनियम अधिसूचित किए थे. नवीनतम सरकारी निर्णय के साथ, यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को अब एनपीएस के समान ही योगदान पर कटौती और अन्य कर-बचत प्रोत्साहन प्राप्त होंगे, जिससे यह योजना वित्तीय रूप से अधिक आकर्षक बन जाएगी.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कर ढांचे के तहत यूपीएस का समावेश पारदर्शी, लचीले और कर-कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयास में एक और कदम है. यह निर्णय दोनों योजनाओं के बीच समानता लाता है और कर्मचारियों को यूपीएस का चयन करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है.

> एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के साथ एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक अनुमानित और सुरक्षित सेवानिवृत्ति आय प्रदान करना है. यूपीएस एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है, जिसमें सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5 प्रतिशत योगदान करती है, जबकि कर्मचारी 10 प्रतिशत का योगदान करता है. इस योजना को नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को बदलने और मौजूदा एनपीएस सदस्यों को इसमें शामिल होने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

सरप्लस लिक्विडिटी पर आरबीआई की सर्जरी

बैंकिंग सिस्टम में था रु. 4.04 लाख करोड़ सरप्लस

नीलामी में मिली रु.1.70 लाख करोड़ की बोलियां

नई दिल्ली, 4 जुलाई.भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सात दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से 1,00,010 करोड़ रुपए निकाले. इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में वर्तमान में मौजूद अतिरिक्त लिक्विडिटी को कम करना है.

आरबीआई के एक बयान के अनुसार, नीलामी के दौरान उसे 1,70,880 करोड़ रुपए की बोलियां मिलीं.केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा, इसमें से, केंद्रीय बैंक ने 5.47 प्रतिशत की कट-ऑफ दर पर 1,00,010 करोड़ रुपए स्वीकार किए. इस कदम से सरप्लस लिक्विडिटी कम होने की उम्मीद है और इससे शॉर्ट-टर्म ओवरनाइट रेट में वृद्धि हो सकती है. आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 3 जुलाई तक बैंकिंग सिस्टम में लगभग 4.04 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सरप्लस था.

पिछले लिक्विडिटी अवशोषण प्रयासों के बावजूद, सिस्टम सरप्लस में रहा, जिसका मुख्य कारण महीने के अंत में वेतन और पेंशन संवितरण जैसे सरकारी प्रवाह थे. इसके अलावा, सरकारी बॉन्ड और कूपन पेमेंट के रिडम्पशन ने अधिक लिक्विडिटी बढ़ाई. पिछले सप्ताह ही, रिजर्व बैंक ने इसी तरह की वीआरआरआर नीलामी के माध्यम से सिस्टम से 84,975 करोड़ रुपए निकाले थे.

> आरबीआई नियमित रूप से सिस्टम में लिक्विडिटी का प्रबंधन करने और शॉर्ट-टर्म इंटरेस्ट रेट को अपनी मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप रखने के लिए वीआरआरआर नीलामी आयोजित करता है. इस बीच, केंद्रीय बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया कि वे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और एमएसई द्वारा लिए गए फ्लोटिंग रेट लोन और एडवांस पर कोई प्री-पेमेंट शुल्क न लगाएं.

सेल ने दुबई में खोला नया ऑफिस

वैश्विक विस्तार की दिशा में सेल की बड़ी छलांग

नई दिल्ली, 4 जुलाई.भारत के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दुबई में अपने प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है. मध्य पूर्व में यह सेल का पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है. इससे वैश्विक स्तर पर कंपनी की उपस्थिति मजबूत होगी.

केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस कार्यालय का उद्घाटन दुबई में भारत के महावाणिज्यदूत सतीश कुमार सिवन, सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमरेंदु प्रकाश, एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी, इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव वी.के. त्रिपाठी और सेल, इस्पात मंत्रालय, एनएमडीसी और मेकॉन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया.

ड्रोन रक्षा क्षेत्र में एवीपीएल की छलांग

नयी दिल्ली,04 जुलाई.ड्रोन विनिर्माण एवं प्रशिक्षण कंपनी एवीपीएल इंटरनेशनल ने रक्षा ड्रोन के अनुसंधान एवं विकास के लिए 10 लाख डॉलर के निवेश की शुक्रवार को घोषणा की.कंपनी ने अप्रैल 2025 तक ड्रोन प्रशिक्षण एवं विनिर्माण के लिए 1.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई थी. बयान के अनुसार, निवेश भारत के ड्रोन परिवेश में महत्वपूर्ण अंतराल से निपटने पर केंद्रित है, जैसे कि आयातित घटकों पर निर्भरता कम करना, बेहतर ड्रोन विकसित करना और महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा के लिए स्वदेशी 'काउंटर-यूएएस' क्षमताओं का निर्माण करना है.यह निवेश एवीपीएल के बिहार और हिसार स्थित संयंत्रों में विनिर्माण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में भी योगदान देगा.

दोपहिया वाहनों के निर्यात में 35% वृद्धि :

यात्री वाहन बिक्री में 7-8 प्रतिशत सालाना गिरावट दर्ज

महिंद्रा, टाटा, हुंडई और मारुति के निर्यात में तेज़ी

नई दिल्ली, 4 जुलाई- एक्सिस सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में दोपहिया (2W), वाणिज्यिक वाहन (CV) और यात्री वाहन (PV) खंडों में निर्यात वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, जबकि घरेलू बिक्री में मिलाजुला रुझान देखने को मिल सकता है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि जून 2025 में, समग्र घरेलू दोपहिया उद्योग में थोक बिक्री की मात्रा में मामूली 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. यह मुख्य रूप से निर्यात में 35 प्रतिशत की मजबूत साल-दर-साल वृद्धि के कारण था. हालांकि, घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में 3 प्रतिशत की गिरावट आई, जो निर्यात और घरेलू बाजार के प्रदर्शन के बीच अंतर को दर्शाता है.

रिपोर्ट में कहा गया है, दोपहिया/ वाणिज्यिक वाहन/ यात्री वाहन में निर्यात वृद्धि जारी है; घरेलू बाजार में मिलाजुला रुझान है. जून 2025 की थोक बिक्री की मात्रा- समग्र घरेलू दोपहिया उद्योग में निर्यात में बेहतर प्रदर्शन के कारण बिक्री में 2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई. यात्री वाहन खंड में जून 2025 में घरेलू बिक्री में 7-8 प्रतिशत की साल-दर-साल गिरावट देखी गई. यह हुंडई, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी जैसे प्रमुख ओईएम द्वारा कम बिक्री के कारण हुआ.

> रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026 में वाणिज्यिक वाहन खिलाड़ियों के लिए सपाट से कम एकल अंकों की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो बस खंड में मजबूत मांग से प्रेरित है. दोपहिया वाहनों का निर्यात वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 22 प्रतिशत साल-दर-साल बढ़ा, भले ही घरेलू उद्योग में 6 प्रतिशत की साल-दर-साल गिरावट आई. रिपोर्ट ने घरेलू दोपहिया मांग के लिए संभावित वृद्धि के कारकों की पहचान की, जिनमें ग्रामीण मांग में वृद्धि, नए उत्पाद लॉन्च, खपत के लिए सरकारी समर्थन (जैसे मध्यम वर्ग के लिए कर राहत), और ओईएम द्वारा इन्वेंट्री भरना शामिल है.

टाटा पावर रूफटॉप सोलर में रिकॉर्ड

नयी दिल्ली, 04 जुलाई (वार्ता) टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 416 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 45,589 रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना की. पिछले साल कंपनी ने इसी अवधि में 8,838 रुफटॉप सौर इंस्टॉलेशन लगाये थे. इस तरह कंपनी ने इस काम में साल-दर-साल 416 प्रतिशत की वृद्धि के साथ चमत्कारिक प्रदर्शन किया है.वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के अंत तक टीपीआरईएल ने देश भर में कुल 2,04,443 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन स्थापित किये थे, जिसकी कुल मिलाकर स्थापित क्षमता 3400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से अधिक बतायी गयी है.

इंडियन ऑयल के पंप अब सौर चालित

हरदीप पुरी बोले — ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली, 4 जुलाई. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है और इसमें सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने 36,000 से अधिक खुदरा आउटलेट्स को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित करके भारत की इस ताकत का विस्तार किया है, जहां अधिकांश परिचालन सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह सराहनीय प्रयास न केवल बिजली बिलों को कम करता है बल्कि 'हरित भारत' के निर्माण में भी अमूल्य योगदान देता है. उन्होंने कहा, नया भारत अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के पूरक पहलुओं के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है. चाहे घर की छत हो, दफ्तर हो या फैक्ट्रीज अगर थोड़ी सी भी जगह है, तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें. यह ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा साधन साबित हो रहा है.

> सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में विस्तार को सौर सेल और वेफर्स के मजबूत घरेलू उत्पादन का समर्थन प्राप्त है, जो 2014 में लगभग न के बराबर था. भारत ने अब 25 गीगावाट सौर सेल उत्पादन और 2 गीगावाट वेफर उत्पादन के साथ एक मजबूत आधार तैयार कर लिया है. इसके अलावा पुरी ने कहा कि दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या वित्त वर्ष 2013-14 में 3 .6 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 .5 करोड़ हो गई है.

भारतीय शेयर बाजारों में हल्का सुधार दिखा

मुंबई, 04 जुलाई (वार्ता) वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों तथा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के रुख के बीच शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में दो दिन की गिरावट से उबर कर तेजी दिखी और उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में प्रमुख सूचकांकों में हल्का सुधार दर्ज किया गया. बीएसई का 30 प्रमुख शेयरों वाला सेंसेक्स तेजी की धारणा के साथ खुलने के बाद दोपहर को नीचे चला गया था. सेंसेक्स अंत में कल के मुकाबले 193.42 अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,432.89 अंक पर बंद हुआ.

सीमेंट सेक्टर में बढ़ी मांग की उम्मीद

वित्त वर्ष 2026 में 7-8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 4 जुलाई.भारतीय सीमेंट क्षेत्र में मांग वित्त वर्ष 2026 में 7-8 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है और संरचनात्मक कारकों के कारण यही मांह वित्त वर्ष 2026-29 में 6 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ेगी. यह जानकारी शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई.

बीएनपी परिबास इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमतों में तेजी से सुधार हुआ है और मानसून के जल्दी आने के बावजूद कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन मौजूदा स्तरों पर कीमतों की स्थिरता वित्त वर्ष 2026 की लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है.विश्लेषक निरांश जैन ने कहा, हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री प्लेयर्स द्वारा लाभप्रदता को प्राथमिकता दिए जाने और उद्योग के निरंतर कंसोलिडेशन के कारण प्राइसिंग पावर में सुधार होगा.

समाचार विशेष

ओवैसी ने सेट कर दिया बिहार का चुनावी प्लान

किसे होगा तगड़ा नुकसान?

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे सभी पार्टियों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है. अब बिहार चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने नई चाल चली है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने 15 दिन पहले ही राजद और कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों को संदेश भेजा था. इसमें उन्होंने कांग्रेस-राजद और वाम दलों के महागठबंधन में शामिल होने की बात कही थी.

अख्तरुल ईमान ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन से समझौता न होने की स्थिति में तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि हम कुछ दलों से बातचीत कर रहे हैं. तीसरे मोर्चे के लिए किन दलों से बातचीत चल रही है, इस सवाल पर ईमान ने किसी दल का नाम लेने से इनकार कर दिया. जब उनसे पूछा गया कि क्या एआईएमआईएम ने 2020 का चुनाव उन दलों में से किसी के साथ लड़ा था, क्या उनसे बातचीत चल रही है? इस सवाल पर ईमान ने हां में जवाब दिया. लेकिन उन दलों का नाम लेने से इनकार कर दिया. ईमान ने कहा कि यह प्रस्ताव बिहार के हित में, बिहार की नई पीढ़ी के हित में, बिहार के भविष्य के हित में और बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए दिया गया है.

महागठबंधन को दिया था प्रस्ताव- उन्होंने कहा कि महागठबंधन से धोखा खाने के बाद भी हमने यह प्रस्ताव दिया है. जब ईमान से पूछा गया कि क्या प्रस्ताव में सीटों की संख्या का भी जिक्र है, तो ईमान ने कहा कि नहीं, सीटों की संख्या को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि 2020 में महागठबंधन ने 112 सीटें जीती थीं और एआईएमआईएम ने पांच सीटें जीती थीं,

महाराष्ट्र में ओवैसी ने किया जिक्र

दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को महाराष्ट्र के परभणी में आयोजित एक रैली में इस प्रस्ताव का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि अख्तरुल ईमान ने प्रस्ताव भेजा था कि अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकना है तो हमारे साथ आकर हाथ मिला लें. लेकिन इस पर फिलहाल बात बनती नज़र नहीं आ रही है. एआईएमआईएम ने 2020 का विधानसभा चुनाव ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फंट में शामिल होकर लड़ा था. इन चुनावों में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और पांच पर जीत हासिल की. हालांकि उसके चार विधायक बाद में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए. अब अगर एक बार फिर तीसरा मोर्चा बना तो एनडीए में जेडीयू और महागठबंधन में आरजेडी को नुकसान हो सकता है.

वक्फ पर विपक्ष की सक्रियता का नुकसान

पटना. विपक्षी पार्टियां अपना नुकसान कर रही हैं. बिहार में राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुस्लिम संगठन इमारत ए शरिया ने वक्फ कानून के खिलाफ रैली का आयोजन किया तो विपक्ष के सारे नेता उसमें शामिल होने पहुंचे. सबने बढ़ चढ़ कर बयानबाजी की.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी कि यह किसी के बाप का देश नहीं है. कांग्रेस की ओर से सलमान खुर्शीद, अखिलेश प्रसाद सिंह, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार सहित एक दर्जन नेता पहुंचे. कांग्रेस के संबद्ध सदस्य और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी खूब जोरदार भाषण दिया. लेकिन इसके क्या हासिल होना है? जानकार सूत्रों का कहना है कि विपक्षी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम से चिंतित हैं. उनको लग रहा है कि जैसे पिछली बार एमआईएम ने पांच सीटें जीत ली थीं और विपक्षी गठबंधन को सीमांचल के इलाके में नुकसान पहुंचाया था. उसी तरह अगर वक्फ का मुद्दा उठा कर वह अकेले लड़ेगी तो इस बार भी नुकसान होगा. लेकिन वास्तविकता अलग है.

> इस बार मुसलमानों को लग रहा है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है तो वे पूरी तरह से विपक्ष के साथ हैं. लेकिन वक्फ पर इतने गरजने बरसने का नुकसान यह है कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को ध्रुवीकरण कराने का मौका मिल रहा है. भाजपा ने तेजस्वी के भाषण को तोड़ मरोड़ कर उसके मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं. यह तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि संसद भवन से लेकर नई दिल्ली के हवाईअड्डे और पटना के गोविंदपुर गांव की हजारों एकड़ जमीन वक्फ को दे दी जाएगी. यह संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर विपक्ष को बहुत आक्रामक होकर राजनीति नहीं करनी चाहिए.

विशेष | **सीएम योगी ने खोजी अखिलेश के पीडीए की काट**

बीजेपी सपा से छीन लेगी उसका सबसे बड़ा वोट बैंक

लखनऊ. भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनावों से पहले सपा के पीडीए की काट का बड़ा दांव निकाला है. विधानसभा चुनावों से पहले पंचायत चुनावो में सभी दल जोर आजमाइश करेंगे.

बीजेपी ने पंचायत चुनावों में ही सपा के सबसे बड़े वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है. बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा पंचायत चुनावों में 2000 प्रधान पद और 120 जिला पंचायत सदस्य पद पर मुस्लिमों को समर्थन देकर लड़ाने की तैयारी में है.

बीजेपी की रणनीति है कि मुस्लिम बहुल्य पंचायतों में मुस्लिम प्रत्याशियों को समर्थन देकर चुनाव लड़ाया जाए, दरअसल बीजेपी इस बात को जानती है कि पंचायत चुनावों में कई ग्राम सभाएं और जिलापंचायत की सीटें ऐसी हैं जहां बिना मुस्लिमों के चुनाव जितना आसान नहीं है. ऐसे में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने तय किया है कि इन प्रधानी और जिला पंचायती की सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को बीजेपी बाहर से समर्थन देगी.

हो सकता है विपक्षी दलों का बड़ा नुकसान

> बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने अपने मोर्चे को सक्रिय कर गांव और जिला पंचायतों से सूची तैयार करानी शुरू कर दी है, जहां मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी के सहयोग से चुनाव जीत सकते हों.यह सूची लगभग तैयार हो रही है. बीजेपी की रणनीति के पीछे मंशा यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ 40 प्रतिशत अकेले मुस्लिम समाज को मिल रहा है यानी कि सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग मुस्लिम समाज है. अब अगर बीजेपी इस मुस्लिम लाभार्थी वर्ग को अपने साथ 10 प्रतिशत भी सहेज पाई तो सपा समेत अन्य विपक्षी दलों का बड़ा नुकसान होगा. यूपी में पंचायत चुनाव वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव से पहले हैं. ऐसे में पंचायत चुनावों को बीजेपी ने अपने मुस्लिम फॉर्मूले की प्रयोगशाला बनाने की तैयारी की है.

पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज नाम से बना नया गठबंधन

श्रीनगर. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में एक नए राजनीतक गठबंधन का एलान किया. इस गठबंधन का नाम पीपल्स एलायंस फॉर चेंज रखा गया है.

गठबंधन में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस,पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट शामिल है. इस सिलसिले में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में फ्रंट की घोषणा करते हुए सज्जाद लोने ने कहा कि आज हम जिस गठबंधन की घोषणा कर रहे हैं वह उन राजनीतिक गठबंधनों का विकल्प होगा जिन्होंने हम पर शासन किया है. हमारा यह गठबंधन एक चुनावी गठबंधन है और यह जनता के सभी मुद्दों को उजागर करेगा. सज्जाद ने आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि भर्ती अधिकारियं द्वारा लगातार सूची जारी की जा रही है और हम जो कहते आ रहे हैं, यह संख्यीकीय रूप से सही साबित हो रहा है इसकी मिसाल हाल ही में जारी जूनियर असिसटेंटों की सूची में 26 में से केवल 5 कश्मीरी हैं.